राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 36 अंक 4 जून-जुलाई 2015 मूल्य 5 रु. पृष्ठ 32

दीप प्रज्वलन कर बैठक का उद्घाटन करते राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरीकर। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. नागेश ठाकुर और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर

रा. का. प. बैठक के नागरिक अभिनंदन समारोह में पुस्तिका का विमोचन करते हुए मान्यवर

पश्चिम बंग में केन्द्रीकृत ऑनलाइन एडमीशन प्रणाली के लिए प्रदर्शन करते अभाविप के कार्यकर्ता

अभाविप द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पारित प्रस्तावों का विमोचन करते (बाएं से) राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. नागेश ठाकुर तथा केन्द्रीय सचिवालय के सचिव श्री चेतस सुखड़िया

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मण्डल

आशुतोष

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-23216298

ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com

वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली - 110007 से प्रकाशित एवं 102, एल. एस. सी., रिषभ विहार मार्केट, दिल्ली-92.

संपादकीय कार्यालय

''छात्रशक्ति भवन''

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
संपादकीय	4
अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुआ गहन मंथन	6
कोलकाता में स्किल इंडिया 2015 का आयोजन	9
वादे नहीं मजबूत इरादे – अवनीश सिंह	11
CLAT विषय पर छात्रों के साथ न्याय करें – श्रीहरि बोरिकर	14
साक्षात्कार – श्रीहरि बोरिकर	15
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बैकडोर से भर्तियां	17
सरस्वती नदी–अंत: सलिला होने को मिला बल – दीपक बरनवाल	18
रा. का. प. बैठक में पारित प्रस्ताव	20
ईशान्य मुंबई में 'समुराई' समर कैम्प का आयोजन	23
हम सब जन्म से योगी – श्री श्री रविशंकर	24
म. प्र. में अभाविप की मांग पर प्रवेश तिथि बढ़ी	26
डीयू के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में अभाविप ने मांगा प्रिंसिपल से इस्तीफा	30

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जुलाई माह विद्यार्थियों के लिए उल्लेखनीय होता है। प्रायः पूरे देश में सत्रांत के बाद एक बार पुनः प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उम्मीद और निराशा का मिला–जुला दौर विद्यार्थियों में व्याकुलता बनाए रखता है। कैरियर के प्रति माता–पिता का आग्रह और दौड़ में पिछड़ने का भय अतिरिक्त तनाव की सृष्टि करता है। इस दौर में ही कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की आत्महत्या की खबरें भी आती हैं। शिक्षा के उद्देश्य, उसके बाजारीकरण, शिक्षा जगत की चुनौतियां और व्यवस्था की कठिनाइयों पर भी ऐसे समय में चर्चा होती है जो कुछ समय बाद ठंडी पड़ जाती है।

गत छः दशकों में शिक्षा को जिस दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है उ… विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न करने और सामाजिक सरोकारों से काटने का ही काम किया है। खास तौर पर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को काफी हद तक बाजार के हवाले कर दिया गया है। बाजार देश के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सस्ती श्रम शक्ति का उत्पादन शिक्षा के इन सस्थानों में करता है। मानवीय मूल्य यहां अपना अर्थ खो देते हैं।

केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति में भारतीयता को सशक्त करने वाले तत्व जोड़ने का मन बनाया है किन्तु इसकी घोषणा से पहले ही इसका राजनैतिक विरोध प्रारंभ हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिक्षा के उद्देश्य को लेकर सदैव से यह मान्यता रही है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का जागरण है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना यह समकालीन परिस्थितियों में आवश्यक है। किन्तु यह उसके उद्देश्य का एक पहलू मात्र है। ज्ञान की भारतीय परंपरा के चिरंतन प्रवाह को नयी पीढ़ी तक पहुंचाना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे किसी भी स्तर पर शिक्षा से अलग नहीं किया… सकता।

हाल ही में सम्पन्न परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में शिक्षा के साथ ही अनेक समकालीन विषयों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किये गये। इस अंक में उन सभी प्रस्तावों को यथारूप संकलित किया गया है। साथ ही देश भर में संगठन की गतिविधियों का बैठक में प्रस्तुत वृत्त भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया।

इसके साथ ही देश में नयी सरकार के एक साल पूरे होने पर जनअपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार की नीतियों का रिसाव अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिये लगातार प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी नीतियों की स्पष्टता और योजनाओं के क्रियान्वयन से जन कसौटी पर अपनी सरकार को खरा साबित करने में जुटे हैं। कई ऐसी विषम परिस्थितियों में इस सरकार द्वारा लिए गये

त्वरित निर्णयों ने जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता को और प्रगाढ़ किया है। इस अंक में मोदी सरकार के वादे नहीं बल्कि एक साल में किये गये कार्यों की रिपोर्ट को भी संकलित किया गया है।

आधुनिक युग ने मनुष्य को इतना प्रायोगिक बना दिया है कि वह हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की कोशिश करता है। अगर उसका मस्तिष्क उस बात को मान लेता है तो वह उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। विज्ञान के कामयाब सफर ने आज मनुष्य की जिंदगी को आसान और खूबसूरत बना दिया है। लेकिन इन सबके बीच कहीं न कहीं हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। काम को लेकर बढ़ता तनाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दिनचर्या पर भी असर डाल रहा है। ऐसे में हर कोई शांति और सादगीपूर्ण जीवन की तलाश में है। ऐसे में योग की तरफ लोगों का रुझान बहुत तेजी से देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भारत में शानदार आयोजनों को लेकर पूरे विश्व में चर्चा रही। इस अंक में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी के संदेश को भी सम्मिलित किया गया है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में कार्य कर रहे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नौ जुलाई को अपनी स्थापना के पैसठ साल पूरे कर लिये है... सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों को शुभकामना सहित –

अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुआ गहन मंथन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की तीन दिवसीय बैठक 27 से 29 मई तक महाराष्ट्र के संभाजीनगर (औरंगाबाद) में सम्पन्न हुई। इसमें पूरे देशभर से 249 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तीन दिवसीय इस महत्वपूर्ण बैठक के पहले अभाविप की केन्द्रीय कार्यसमिति एवं अभाविप के विकासार्थ विद्यार्थी, थिंक इंडिया, केन्द्रीय विवि, जनजाति कार्य, मेडिविजन (एजोपैथी), जिज्ञासा (आयुर्वेद), सांस्कृतिक समूह, छात्रा कार्य एवं कृषि छात्र 9 आयामों की बैठक 26 मई को हुई।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक का प्रारंभ करते हुए डॉ. नागेश ठाकुर ने अपने प्रास्ताविक भाषण में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि 1949 से आज तक अनेक प्रकार की चुनौतियों से संघर्ष करते हुए हमने कई सफलताएँ भी हासिल की है। हमने अपने दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी किया है। हमने "नशा मुक्त, पर्यावरण युक्त, स्वच्छ भारत अभियान" सफलतापूर्वक चलाया है। गत एक वर्ष में छात्रा सहभाग, छात्राओं की गतिविधियाँ बढ़ी है। 1982 के दशक से अखिल भारतीय विचार बैठक लगातार हो रही है। हर 4–5 वर्ष बाद पर यह बैठक होती है और अभी अप्रैल, 2015 में पुष्कर (राजस्थान) में यह बैठक सम्पन्न हुई। वर्तमान केन्द्र सरकार नई शिक्षा नीति बना रही है। हम सभी का सहयोग लेना यह स्वागत योग्य कदम है। हम कई लोगों से चर्चा कर इस पर काम कर रहे है। लगभग देश के 20 स्थानों पर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। आज भारत सक्षमता से दुनिया में आगे बढ़ रहा है। साथ ही यह बैठक ऐसे में समय हो रही है जब नक्सल गतिविधियाँ एक बड़ी चुनौती बन गयी है। जिसके समाधान के लिए एक कठोर नीति बनाने की आवश्यकता है। भारत को आगे बढ़ाने हेतु अधिकतम युवाओं को भारतमाता की सेवा में लगना पड़ेगा।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक की पूर्व संध्या पर दिनांक 26 मई को संभाजीनगर (औरंगाबाद) में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. वी. ए. चोपड़े ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है योग्य शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वहाँ मुलभूत संरचना खड़ी करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर ने इस कार्यक्रम में कहा उच्च शिक्षा में परिवर्तन की जरूरत है। और हमारे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति को छोड़कर भारतीय शिक्षा पद्धति पर बल देना चाहिए। राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि, इस ऐतिहासिक नगरी में हम आने वाले विविध विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए कुछ निर्णय लेंगे जो भविष्य में मार्गदर्शक साबित होंगे। अपने वक्तव्य में उन्होंने आंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन जो विद्यार्थी परिषद् का एक अनुपम प्रकल्प है उसकी 50 वर्ष पूर्ति हेतु सालभर देश भर में होने वाले विविध कार्यक्रमों में सहभागी होने एवं मदद करने का आवाहन किया।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श हुआ। गहन मंथन के बाद महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रस्तावों में शामिल किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् केन्द्र सरकार की नयी शिक्षा नीति में कुछ बदलाव चाहती है। इसको लेकर अभाविप ने प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को सौंपा है। सरकार को सौंपे गए प्रस्ताव पर प्रो. मिलिन्द मराठे ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने नयी शिक्षा नीति में प्रशासनिक सुधार के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मसलन

शैक्षाणिक गुणवत्ता बढ़ाने, मान्यता देने वाली प्रणाली में सुधार, केन्द्रीय व प्रादेशिक शैक्षणिक संस्थानों को सशक्तिकरण, कौशल विकास पर विशेष जोर, पत्राचार द्वारा पढ़ाई, गुणवत्तापरक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान, भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा का प्रावधान हो, जिसमें सांस्कृतिक अखंडता, सामाजिक–लैंगिक भेदभाव संबंधी समस्याओं के निदान का प्रावधान हो। उच्चतर शिक्षा को आवश्यकतानुसार वित्त मिलना चाहिए। इसके अलावा अनुसंधान अध्ययन पर विशेष जोर के साथ कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

अभाविप संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने अभाविप के दस साल के सांगठनिक कार्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में अभाविप के सदस्यों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई। अलग–अलग प्रांतों में भिन्न–भिन्न तरीके, योजना और समय–काल का ध्यान रखते हुए सदस्यता अभियान चलाया। अकेले आंध्रप्रदेश की इकाई ने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाकर एक दिन में एक लाख नए सदस्य बनाए। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद की योजना अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचने की है। इसके लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के शैक्षणिक क्षेत्रों की संस्थानों और विद्यालयों से सम्पर्क करने की योजना है।

नेपाल में राहत कार्यों में भूमिका : नेपाल में अचानक आये भयंकर भूकम्प ने भारी जन और धन को नुकसान पहुंचाया। विद्यार्थी परिषद् नेपाल के भूकम्प पीड़ितों के साथ खड़ा रहा और तुरंत राहत में लग गया। इस कार्य के बारे में प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रमेश कन्डले ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने बिना दिन–रात देखे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में काम किया। उन्होंने कहा कि नेपाल के लोगों को जो भावनात्मक सहयोग प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद से मिला, वह सराहनीय है।

आंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन (SEIL–सील) यात्रा –2015 :– अंतरराष्ट्रीय छात्र जीवन दर्शन के 50 वर्ष पूरे होने पर सील की जानकारी तथा वर्षभर के कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने सबको अवगत कराया। यह सील–50 वर्ष की मुख्य संकल्पना 'पूर्वोत्तर को जानो– भारत जानो' रहेगी। साथ ही स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत दिल्ली, गुवाहटी व मुंबई में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों में स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रमों का आयोजन। 'पूर्वोत्तर के विकास में युवाओं के व्यापक सहभाग' हेतु विभिन्न जनजाति छात्र नेताओं का सम्मेलन। सील यात्रा–2016 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 250 छात्र–छात्राओं की देशव्यापी 'राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा'। 'पूर्वोत्तर को जानो– भारत जानो' देशव्यापी जागरण अभियान के अन्तर्गत प्रदर्शनी, लघु चित्रपट, सेमिनार/संगोष्ठियों आदि का आयोजन होना निश्चित किया गया है।

संगठनात्मक विवरण

	2014–15	2013–14	कुल वृद्धि
इकाई	2715	2146	569
संपर्क स्थान	2016	1622	394
विस्तार केंद्र	953	972	–19
महा. इकाई	7126	5946	1180
सदस्यता	3175753	2249493	926260

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक में सर्व सम्मति से पांच प्रस्ताव पारित हुए।

पहले प्रस्ताव में अभाविप ने देशभर के प्रादेशिक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की हालात पर चिंता व्यक्त की। अभाविप ने केन्द्र व राज्य सरकारों से अधिक वित्तीय सहायता देकर आवश्यक संसाधनों

की पूर्ति करने की मांग की।

दूसरे प्रस्ताव में अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा इराक और यमन में भारतीय व विदेशी नागरिकों को सकुशल बाहर निकालने को कूटनीतिक जीत बताया। साथ ही नेपाल में हुए भुकंप के पश्चात् तत्काल राहत कार्य पहुंचाने को सराहा। सरकार द्वारा जनधन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को गरीबी और महिलाओं के हित में उठाए गए कदमों को सराहनीय माना। बिहार में फैली शिक्षा में अराजकता के विरूद्ध अभाविप के विरोध प्रदर्शन पर नीतीश सरकार द्वारा बर्बर लाठी चार्ज के कार्रवाई की निंदा की।

तीसरे प्रस्ताव में देशभर में सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे एससी और एसटी छात्रावासों की खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त की। अभाविप द्वारा इसी विषय पर दायर की गई याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2015 को दिए निर्णय जिसमें उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को इस अव्यवस्था को ठीक करने के आदेश का विद्यार्थी परिषद् स्वागत करती है। साथ ही छात्रों की छात्रवृत्ति को दूसरे मद में खर्च करने के राज्य सरकारी एवं विश्वविद्यालयों को कड़ा विरोध करती है।

चौथे प्रस्ताव में देश में कौशल संवर्धन द्वारा रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना को लागू किये जाने की मांग की तथा पारंपारिक पेशे से जुड़े विभिन्न व्यावसायों से अर्जित कौशल को स्थापित किए जाने की मांग की।

पांचवे प्रस्ताव में शिक्षा में बढ़ते व्यापारीकरण पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक और केन्द्रीकृत कानून बनाने की मांग की गई।

आगामी कार्यक्रमों में 27 से 29 नवंबर में अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन भुवनेश्वर में होगा। इसके अलावा स्वर्ण जयन्ती वर्ष यात्रा ढाई सौ विद्यार्थियों के साथ पूरे देशभर में की जाएगी। साथ ही छात्रा सम्मेलन, जनजातीय छात्र एवं यूथ पार्लियामेंट आगामी समय में दिल्ली में आयोजित होगी। लखनऊ में विधि छात्रों का सम्मेलन कराया जाएगा।

कार्यक्रमात्मक विवरण

	स्थान	कार्यक्रम	उपस्थिति
राष्ट्रीय छात्र दिवस (9 जुलाई)	1985	3033	443941
सामाजिक समता दिवस (6 दिसंबर)	1294	1541	165550
राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी)	1607	2574	551484

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का जून–जुलाई 2015 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

"छात्रशक्ति भवन,"
26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली – 110002
फोन : 011–23216298
ई–मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाईट : www.abvp.org

कोलकाता में 'स्किल इंडिया-2015' का आयोजन

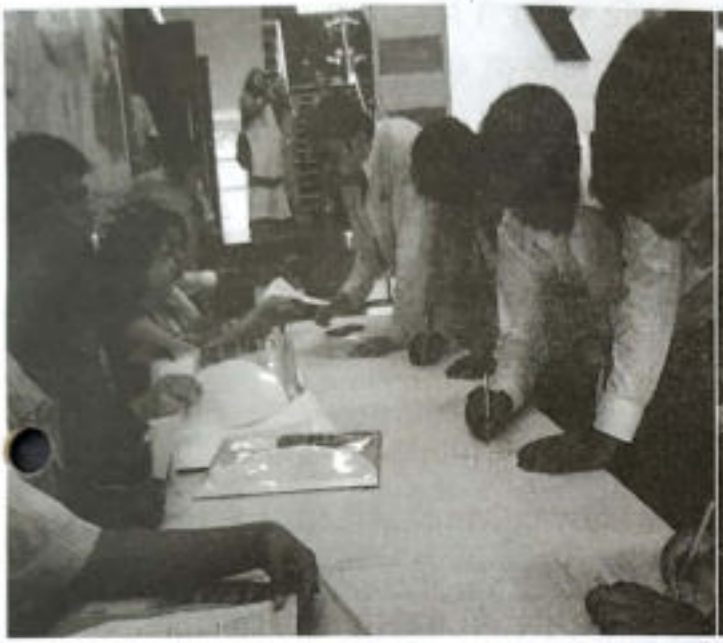

कोलकाता। राष्ट्रीय विकास के लिए स्वदेशी कौशल, उसके विकास और रोजगार के अवसर को लेकर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कोलकाता के मौलाली युवा केन्द्र में 22 मई 2015 को संपन्न हुई। इसमें पश्चिम बंगाल के कई गांवों से आए हुए 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहां आने वाले ज्यादातर प्रतिनिधियों ने www.skillindia2015.in इस बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। कार्यक्रम वंदेमातरम के गायन और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमति निर्मला सीतारामण ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरूआत की।

श्रीमति सीतारामण ने उद्घाटन सत्र के दौरान युवाओं से कहा कि भारतीय युवाओं को प्रासंगिक कौशल के प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके बगैर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने देश की प्रगतिं के लिए स्वदेशी कौशल को समृद्ध बनाने पर बल दिया।

व्यापक रूप से प्रसारित बंगाली साप्ताहिक 'बारतामान' के संपादक श्री रन्तीदेव गुप्ता ने सकिल इंडिया के तहत आयोजित इस सेमिनार के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा इस तरह के कार्यक्रमों के कारण ही अभाविप अन्य छात्र संगठनों से अलग है।

ए एम आर आई अस्पताल के सीईओ श्री रूपक बरूआ ने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुशल मानव शक्ति की बहुत जरूरत है। आई आई ई एस टी सिबलपुर के डायरेक्टर डॉ. अजय रॉय ने भी शिक्षाविदों के साथ पेशेवर कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

सेमिनार के पहले सत्र का विषय 'कौशल भारत और आगे का सच' था। टाटा मेटालिक्ट के पूर्व प्रबंध निदेशक और व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्ष झा ने इस सूत्र की अध्यक्षता की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ दिपांकर दास

गुप्ता ने बताया असल कौशल क्या है। और कैसे हम इसे देश की उत्पादकता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

रत्न और आभूषण निर्यात परिषद् के वाइस चेयरमैन पंकज पारेक ने आभूषण बनाने और रत्नों की कटिंग और पॉलिशिंग में स्वदेशी तकनीको और उसके कौशलता की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे इस कौशल के बदौलत गुजरात के सूरत और पश्चिम बंगाल के अंदुल के लोगों का जीवन बदल रहा है।

विद्यार्थी परिषद् के मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक जुड़ी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए काम करने वाली डॉ. इंद्रानिल खान ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति की बहुत जरूरत है। कुशल मानवशक्ति की आपूर्ति और जरूरत के बीच खाई बहुत बड़ी है। इसे पाटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कई प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शुरू है, जिससे रोजगार की उपलब्धता तेजी से बढ़ेगी।

नासकॉम के पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख श्री सुपर्णा मोइना ने दर्शकों का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं में कौशल का इस्तेमाल जरूरी है। युवाओं के कौशल का कैसे इस्तेमाल हो, इस पर विचार मंथन जरूरी है। उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिभावकों की मानसिकता में बदलाव लाने और सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया।

पहले सत्र के सवाल–जवाब के दौरान सिलिगुड़ी के एक 19 वर्षीय युवा जाग्रत ने बाइक को रिमॉडलिंग कर अपने कौशल का परिचय दिया। स्किल इंडिया के दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्रो. रंजन सेन नेगी ने की जिसका विषय था 'शिक्षा पाठ्यक्रम में कौशल विकास' गौर बंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अचिन्तया विश्वास ने कौशल विकास के जरूरत को ध्यान में रखते हुए परम्परागत अकादमिक डिग्री से इसकी तुलना की।

रामकृष्ण मिशन शिला मंदिर के स्वामी वेदादितानंदा ने विस्तार से बताया कि कैसे उनका संगठन जरूरत के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण पर काम करता है और प्रशिक्षण के बाद विभिन्न उद्योगिक घरानों और प्लेसमेंट के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है।

इग्नू के कोलकाता क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुजीत घोष ने मुख्य धारा को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ अतिरिक्त कौशल पाठ्यक्रमों भी जोड़ कर बेहतर रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री के के गांगुली ने कहा भारत की स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने कौशल को रोजगार में बदलने और हथियार के लिए विदेशों पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सकता है।

दक्षिण कोलकाता के बंगबासी कॉलेज के प्रो. देवाशीष चौधरी ने कहा कि स्वदेशी कौशल में भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा है। हमें अपने कौशल के बदौलत फिर से पुनर्स्थापित करने की जरूरत है।

एक दिवसीय विचार–विमर्श के सेमिनार के अंत में यह बात सामने आई कि स्किल भारत भले ही सरकारी योजना है लेकिन इसे लगातार चलाने जरूरत हैं। और यह तभी संभव है जब कौशल विकास में समाज की भागीदारी बढ़ेगी, इसे सामाजिक पहल के रूप में देखा जाएगा।

सेमिनार के अंत में कौशल और युवाओं के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए इस सेमिनार में आने वाले सभी बंधुओं अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजन समिति द्वारा सभी प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। ■

वादे नहीं मजबूत इरादे

✍ अवनीश सिंह

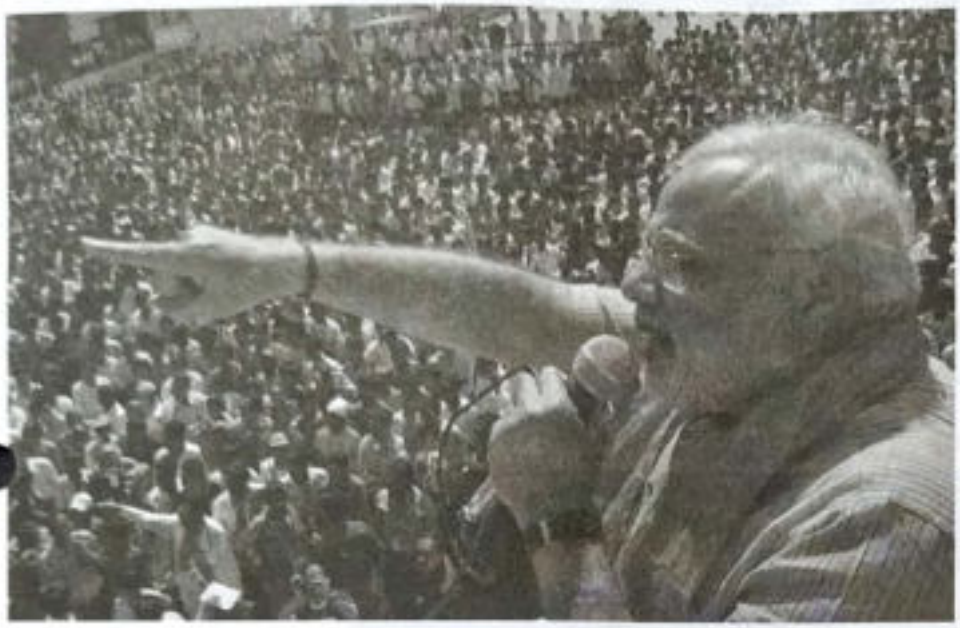

देश जब स्वतंत्र हुआ, अनेक राजनैतिक दल और विचार भारत में सक्रिय थे। प्रायः सभी का लक्ष्य था संघर्ष और अंततः अंग्रेजों से आजादी। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ स्वतंत्र भारत का पहला राजनैतिक दल था जो देश के भविष्य की सोच के साथ उत्पन्न हुआ था। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विश्वास था – "जो देश अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर गर्व का अहसास नहीं कर पाता है, वह अपने वर्तमान या भविष्य का ठीक प्रकार से निर्माण नहीं कर सकता ... एक कमजोर देश कभी भी महानता को प्राप्त नहीं करता"...। अपने पूरे जीवन में उन्होंने देश के गौरव को अक्षुण्ण रखा और राष्ट्रीय एकात्मता की साधना करते हुए बलिदान दिया।

उनके निकट सहयोगी पं दीनदयाल उपाध्याय ने डॉ मुखर्जी के कार्य को आगे बढाया। वे एक राजनैतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भारतीयता के गहन अध्येता भी थे। उन्होंने भारत की चिति तो पहचाना और अंत्योदय का सिद्धांत दिया। जनसंघ ने इसे अपना नीतिनिर्देशक तत्व स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी जब 'सबका साथ – सबका विकास' की बात कहती है तो यह राजनैतिक नारा नहीं बल्कि दीनदयाल जी द्वारा दिये अंत्योदय के सूत्र की पुनर्अभिव्यक्ति ही है।

सरकार की नीतियों का रिसाव अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिये चाहिये नीतियों की स्पष्टता, संकल्पबद्ध सरकार और सक्रिय कार्यपालिका। सुशासन इसकी पहली शर्त है। 1998 में राजग सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के सम्माननीय नेता मान्यवर अटल जी ने इस कसौटी पर अपनी सरकार को खरा साबित करने के प्रयत्न किये। गठबंधन की सीमा के चलते इन प्रयासों को तार्किक परिणति तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिल सका। किन्तु उनके द्वारा की गयी पहल वर्तमान सरकार के लिये आधारशिला बनी। जनसंघ की स्थापना से आज तक दिशा और दर्शन की निरंतरता बनाये रखते हुए उत्तरदायी शासन प्रणाली विकसित करने तथा कार्यपद्धति और कार्यसंस्कृति में अपेक्षित बदलाव कर अंत्योदय की दिशा में वर्तमान मोदी सरकार बढ़ रही है।

यह सर्वमान्य है कि भारत गांवों में बसता है। देश समृद्ध बनता है गांवों की खुशहाली से। और गांव की खुशहाली का आधार है भरपूर फसल। सरकार ने हर खेत को पानी के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की है ताकि 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' मिल सके। राज्य सरकारों को साथ लेकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना के अंतर्गत खेतों को पर्याप्त बिजली पहुंचाने का प्रयास भी अब अपना असर दिखाने लगा है।

समाज की मूल इकाई है परिवार। परिवार में किसी के साथ भी कोई अनहोनी होने पर अब आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक में 2 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा हासिल है। दुर्घटना बीमा के लिये मात्र 1 रुपया प्रतिमाह और जीवन बीमा के लिये केवल 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।

वरिष्ठ नागरिकों का जीवन शांति और निश्चिंतता के साथ बीत सके इसके लिये 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। आरंभिक अंशदान जमा करने पर 15 वर्ष तक मासिक पेंशन मिलेगी जिसके बाद जमा की गयी राशि वापस लौटा दी जायेगी। वृद्ध आयु वाले पेंशनधारकों, बीपीएल परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम भुगतान में सब्सिडी देने के लिये एक पृथक कोष बनाया गया है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आयकर छूट की सीमा भी बढ़ाकर 30 हजार कर दी गयी है।

युवाओं को अब खेती की तरह ही स्वरोजगार के लिये भी सस्ता ऋण मिलेगा। सरकार ने इसके लिये मुद्रा बैंक की स्थापना की है। 20 हजार करोड़ रुपये राशि वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु उद्योग प्रारंभ करने अथवा वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिये 10 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकेगा। ऋण लेने वालो को एक मुद्रा कार्ड भी मिलेगा जिसका क्रेडिट कार्ड की तरह उपयोग किया जा सकेगा।

बचत भारत की प्रवृत्ति है। लेकिन इस बचत की सुरक्षा तभी संभव है जब देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाया जाय। साथ ही सरकारी योजनाओं के आर्थिक लाभ नागरिकों तक सीधे पहुंचाने के लिए सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' मिशन प्रारंभ किया। 10 महीनों के रिकॉर्ड अल्पावधि में 11 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुलवाने में सरकार सफल रही है।

सरकार ने कतार में सबसे अंतिम व्यक्ति यानि सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति के कल्याण के विचार को प्राथमिकता देकर जनसाधारण के लिए बीमा और वंचितों के लिए पेंशन की योजना लागू की है। एक ओर मुद्रा बैंक ने उपेक्षित उद्यमियों की चिंताएं मिटाने का रास्ता चौड़ा किया है, तो दूसरी ओर जन–धन के कारण वित्तीय समावेशन अब जमीनी हकीकत बनी है। देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने और प्रत्येक परिवार के लिए बैंक खाता खोलने के लिए सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन – धन योजना' मिशन प्रारंभ किया। 10 महीनों के रिकॉर्ड अल्पावधि में 11 करोड से अधिक बैंक खाते खुलवाने में सरकार कामयाब हुई है। जनसाधारण के लिए भविष्य की चिंता का हरण भी आर्थिक समावेशन का प्रमुख पहलू है। मोदी सरकार ने प्रोविडेन्ट फण्ड के प्रबंधन में अधिक लचिलापन लाया और लाखों वरिष्ठ जनों को राहत दी।

देश का बहुत बड़ा समुदाय वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर जी रहा है। वनवासी समुदाय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभ की हुई 'वनबंधु कल्याण योजना' मील का पत्थर साबित होगी। वनबंधुओं को उनकी वनोपज का ठीक से समर्थन मूल्य मिले इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन भी प्रारंभ की है जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है.... देश में हर नागरिक को सम्मान की पहचान मिले इसके लिए जल्द ही सभी विकलांगों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष पहचान पत्र भी जारी कर रही है।

सरकार ने संवेदनशील सुशासन के लिए कई नए उपाए किए हैं, विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ कमजोर वर्गों को मिले और सब्सिडी वाले अनाज, ईंधन और खाद की योजनाओं में से बिचोलियों का सफाया हो इसलिए इस काम को शुरू किया गया

है। अब गैस खरीदने के पश्चात् बिना किसी परेशानी और भ्रष्टाचार के सब्सिडी की राशी नागरिक के बैंक खाते में आ जाती है... अब तक उन्नीस करोड़ ट्रांजैक्शीन के जरिए लगभग सात हजार करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों में जा चुकी है।

लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए सरकार ने सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने और हलफनामे की झंझट खत्म कर सर्टिफिकेट के "स्व प्रमाणिकरण" को मान्यता दी है और सभी राज्यों से भी इस विषय में अमल का आग्रह किया है। देश की जनता ने एक "जिम्मेदार" सरकार चलाने का जनादेश दिया है... इसलिए सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाकर शासकीय कर्मचारियों की लेट–लतीफी पर अंकुश लगाया गया है। परिणामतः सरकारी कामकाजी घंटों में इजाफा हुआ है।

महिला सुरक्षा देश में एक बड़ा विषय है... माताओं और बहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में भागीदारी बराबरी से हो इस हेतु सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए देश की आधी आबादी (महिला) के लिए दिल्ली सहित सभी संघ शासित प्रदेशों के पुलिस बल में कांस्टेबल से उप निरीक्षक रैंक तक 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी।

सरकार की एक साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों को देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के सामर्थ्य को पुनर्स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण रहा है। नरेन्द्र मोदी के कूटनीतिक प्रयासों का ही परिणाम है कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वार मान्यता मिली। इतना ही नहीं इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना रही।

देश की सीमाओं पर तैनात जवान जब जागता है तो देश की जनता चैन की नींद सोती है। जब समूचा देश अपने घरों में दिवाली मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीमा पर जवानों का हौंसला बढ़ाने के लिए 12 हजार फीट की ऊंचाई पर सियाचीन बेस कैम्प में सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद कर रहे थें।

दस साल के 'गवर्नेंस हॉलिडे' के पश्चात सत्ता संभाली मोदी सरकार को इस बात का अहसास है कि जनता शासन– तंत्र की घिसी – पिटी कार्यशैली से ग्रस्त है। जनता चाहती है उस प्रकार का सुशासन, जहां सरकार के सभी घटक लोगों के प्रति संवेदनशील हो और शासन चलाने में सक्षम भी। इसलिए जरूरी थी, एक नई सोच, नए तौर–तरीके और नई कार्यपद्धती।

मोदी सरकार ने सरकार की पुरानी योजनाओं को एक नया डायमेंशन दिया। आदर्शग्राम योजना को सांसदों से जोड़कर दायित्व सु–निश्चित किया और निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण भी। स्वच्छ भारत को लोक संस्कार का विषय बनाया जिसके कारण स्वच्छता के प्रति सक्रीयता बढ़ी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बैंक ऑफ आइडियाज और इनोवेशन के जरिए नवकल्पना के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित की। जनता के साथ सीधे संवाद को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री अपने मन की बात लोगों के साथ बाटने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही एनडीए सरकार विकास की परीधी में सभी को समाहित कर रही है। यही कारण है कि विकास को गतिशील बनाकर यह सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक नया अध्याय रच रही है। ■

CLAT विषय पर छात्रों के साथ न्याय करें सरकार - श्रीहरि बोरिकर

केन्द्रीय कानून मंत्री श्री सदानंद गौड़ा को ज्ञापन सौंपता अभाविप का प्रतिनिधि मंडल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री सदानंद गौड़ा से मिला तथा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2015 परीक्षा को रद्द कर पुनः करवाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने इस वर्ष हुई परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तथा इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की।

एबीवीपी ने मांग की है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2015 को पुनः आयोजित किया जाना चाहिए ताकि सामान्य विद्यार्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित हो। साथ ही, एबीवीपी ने मांग की है कि एक जांच समिति द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जानी चाहिए। एबीवीपी की मांगो पर केंद्रीय विधि मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि यह विषय कोर्ट में है इसलिए हम कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है लेकिन हम 'बार कौंसिल ऑफ इंडिया' के चेयरमैन से बात करेंगे।

इस विषय पर एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रहरि बोरिकर ने कहा कि जब हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दाव पर है, तब सरकार को इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए विद्यार्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस मसले पर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठा रही है, तथा यह भी आश्चर्यजनक है कि जब देश में लॉ के इतने विद्यार्थी परेशान है तब बार कॉसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विदेश दौरे पर है।

एबीवीपी के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कार्य के प्रमुख श्री वीर विक्रांत सिंह ने कहा कि इस मसले पर एबीवीपी अब अपना आन्दोलन उग्र करेगी तथा सभी NLU मे प्रदर्शन करेंगी।

वहीं CLAT की परीक्षा को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बाम्बे हाईकोर्ट ने सकारात्मक निर्देश दिया है। माननीय कोर्ट ने CLAT के संयोजक को उत्तर पुस्तिका जांच करने का आदेश दिया। इसके लिए सात दिन के भीतर एक विशेषज्ञों का पैनल बनाने को कहा है। ■

अभाविप का मोबाइल ऐप
डाउनलोड
करने की लिंक आपको
ABVP के
अधिकारिक अकाउंट
http://www.facebook.com/ABVPVOICE
https://twitter.com/abvpcentral
पर और वेबसाइट
www.abvp.org
पर भी उपलब्ध रहेगी।

साक्षात्कार

शैक्षिक क्षेत्र में सुधार हेतु एक व्यापक केन्द्रीय कानून की जरूरत

– श्रीहरि बोरिकर

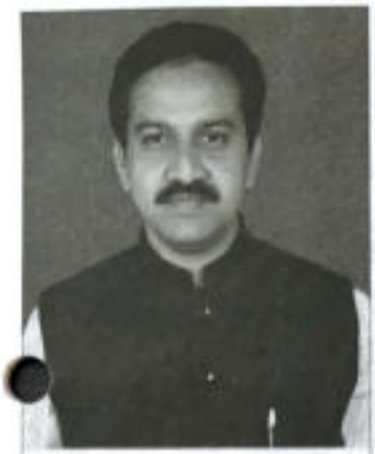
श्रीहरी बोरीकर (राष्ट्रीय महामंत्री)

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन दिनों प्रादेशिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति में सुधार को लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करने जा रहा है। शिक्षा की स्थिति में सुधार, देश के वर्तमान परिदृष्य और शिक्षा के व्यापारीकरण सहित कई मुद्दों पर एबीवीपी के राष्ट्रीय महामन्त्री श्रीहरि बोरिकर से हमारे प्रतिनिधि अवनीश सिंह ने बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश...

वर्तमान समय में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं ?

व्यक्तित्व के समग्र विकास एवं जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख माध्यम शिक्षा है। जिसके लिए पूरे देश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई लेकिन आधारभूत संरचना का अभाव, योग्य शिक्षकों की कमी, छात्र–छात्राओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव और गुणवत्तायुक्त शिक्षा व शोध के अभाव के कारण सभी प्रान्तों के सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए राज्य सरकारों की भूमिका संदिग्ध है, विद्यार्थी परिषद इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार मानती है।

सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को पुनर्स्थापित करने के लिए किस तरह के प्रयास की जरूरत है ?

देश के सर्वाधिक छात्रों को शिक्षा देने वाले इन संस्थानों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों की रचना की जाए, इसके साथ ही कौशल–विकास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो ये संस्थान देश और समाज के विकास हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित हो सकते हैं। विद्यार्थी परिषद इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों से माँग करती है कि राज्य के इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को बुनियादी संरचना के विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वर्तमान शैक्षणिक परिवेश में और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में पहल करे।

इन दिनों बड़े पैमाने पर खुल रहे निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से क्या शिक्षा की पहुंच छात्रों तक बढ़ी है ?

बड़े पैमाने पर खुल रहे निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने शिक्षा को बाजारवाद की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण सरकारी संस्थानों की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। यह कितना दुर्भाग्यजनक है कि जहाँ पूरे देश में पिछले दस वर्षों में नाम मात्र ही कुछ सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में निजी शिक्षण संस्थान अस्तित्व में आ गये जिसके कारण शिक्षा महंगी और छात्रों की पहुँच से दूर हो गयी। छात्र–छात्राएं चाहकर भी पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और व्यापारीकरण पर रोक के लिए विद्यार्थी परिषद क्या कदम उठा रही है ?

प्राचीनकाल से ही भारतीय परम्परा में शिक्षा केवल राज्याश्रित न होकर समाज द्वारा संचालित होती रही

है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में निजी सहभाग को विद्यार्थी परिषद अनुचित नहीं मानती है, लेकिन वर्तमान में निजीकरण के नाम पर शिक्षा का व्यापारीकरण लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक तरफ जहां शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है वहीं दूसरी तरफ यह सामान्यजनों से दूर होती जा रही है। विद्यार्थी परिषद केन्द्र सरकार से शैक्षिक क्षेत्र में बड़े सुधार हेतु एक सम्यक दृष्टि अपनाते हुए एक व्यापक स्तर पर केन्द्रीय कानून लाने की माँग करती है, जिससे शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने तथा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती व सर्वसुलभ बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

केन्द्र की मोदी सरकार को एक साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के कामकाज को आप किस नजरिये से देखते हैं ?

पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद देश में एक सकारात्मक वातावरण बना है। वर्तमान केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों ने भारत का मान दुनियाभर में बढ़ाया है। पिछले दिनों यमन में गृहयुद्ध के दौरान चार हजार से अधिक भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाना सरकार की कूटनीतिक विजय को दर्शाता है। "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ", "जनधन योजना", "स्वास्थ्य बीमा योजना" के साथ ही अन्य महात्वाकांक्षी योजनाओं ने महिलाओं और गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये हैं। नेपाल में आये भूकम्प के दौरान राहत और बचाव कार्य को लेकर भारत सरकार द्वारा दिखाई गयी तत्परता प्रशंसनीय है।

ऐसे में अब जब हर तरफ एक सकारात्मक वातावरण दिखायी दे रहा है तो आप केन्द्र सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं ?

देश के युवाओं ने कई आशाओं व अपेक्षाओं के साथ वर्तमान केन्द्र सरकार को अपार बहुमत से चुनकर सत्तासीन किया है। अभाविप केन्द्र सरकार से अपेक्षा करती है कि युवाओं से किये गये वायदे को पूरा करने व युवाओं के रोजगार हेतु शीघ्र ठोस कदम उठाए व घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। इसके साथ ही विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के संदर्भ में समस्त देशवासियों की अपेक्षाओं को भी वर्तमान केन्द्र सरकार शिघ्र पूरा करे।

मेक इन इंडिया को लेकर अभाविप का क्या मानना है। क्या इससे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ?

देखिये, देश में पैंतीस वर्ष से कम आयु की दो तिहाई जनसंख्या के साथ भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है लेकिन यहां एक चौथाई युवा ही रोजगार के लिए कौशल संमपन्न समझे जाते हैं। अभाविप मानती है कि मेक इन इण्डिया जैसी योजना आने वाले समय में रोजगार के नये अवसर तो पैदा करेगी लेकिन देश के युवाओं में स्वरोजगार और कौशल विकास की कमी को दूर करने के लिए पहले व्यापक स्तर पर कौशल संवर्धन योजना की आवश्यकता है।

युवाओं में कौशल विकास के लिए किस तरह की योजनाओं पर अमल करने की आवश्यकता है ?

विद्यार्थी परिषद मानती है कि युवाओं को उद्यमी एवं रोजगारयुक्त बनाने के लिए 9वीं कक्षा से ही कौशल संवर्धन से जुड़े पाठ्यक्रम चलाने चाहिए तथा महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों में कौशल–संवर्धन के पाठ्यक्रमों को स्वरोजगार के स्थानीय अवसरों को देखते हुए पूरी शक्ति से लागू करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न कारणों से स्कूल या महाविद्यालय की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने वाले युवाओं को कौशल संवर्धन के साथ–साथ स्वरोजगार के लिए आसान किस्तों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए।

जम्मू–कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और सीमा पार से हो रही गोलीबारी को लेकर वहाँ की नवगठित सरकार के रुख से आप कितने संतुष्ट हैं ?

'कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी..' हर परिषद कार्यकर्ता इस नारे की महत्ता को समझता है। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुई परिस्थिति तथा पाक–समर्थित आतंकी हमलों पर अभाविप चिंता व्यक्त करती है।.हुर्रियत की कश्मीर में हुई रैलियों में खुलेआम पाकिस्तानी झंडे लहराना व पाक–समर्थित नारे लगाना, सीमा पार से हो रही गोलीबारी को लेकर जम्मू–कश्मीर की सरकार का लचर रवैया देखने को मिला है, जिसकी हम निन्दा करते हैं। विद्यार्थी परिषद इन मामलों में केन्द्र सरकार से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाने की माँग करती है।

सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी माओवाद पर नकेल नहीं लग पा रही है, आये दिन नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं ?

कई दशकों से देश में चल रहा माओवाद समय–समय पर अपनी देशद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों से नागरिकों में खौफ पैदा कर रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या एवं राष्ट्रविरोधी घटनाएं इसका उदाहरण हैं। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा सहित अन्य जिलों में विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चौबीस हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। अभाविप केन्द्र सरकार से माँग करती है कि माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए। ■

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बैकडोर से भर्तियां

शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश विश्वविद्यालय में हो रही भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एबीवीपी के प्रांत मंत्री आशीष सिक्टा ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर विश्वविद्यालय प्रशासन अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय में बैकडोर से भर्ती करा रहा है। हाल ही एक साक्षात्कार में इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति करने के लिए योग्यताओं में फेरबदल किया गया। अक्टूबर 2014 को आयोजित कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में एडल्ट एजुकेशन के लाइफ लर्निंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने का फैसला हुआ था। इसमें पांच साल का रिसर्च वर्क अनुभव अनिवार्य किया था। पद विज्ञापित हुए तो चर्चाएं तभी शुरू हो गई थी।

उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अनुभव अनिवार्य ही नहीं है। ऐसे में ईसी ने किस आधार पर भर्ती करने का फैसला लिया है। उक्त पद के लिए होने वाले साक्षात्कार को लेकर विश्वविद्यालय में विरोध होना शुरू हो चुका है। इस संबंध में कुछ शिक्षक कुलपति से भी मिल चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने साक्षात्कार को रद्द नहीं किया है। नियमानुसार नेट और सेट उत्तीर्ण उम्मीदवार ही विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षक लग सकते है।

एबीवीपी के मुताबिक फिर भी सीधे साक्षात्कार करवाए जा रहे हैं, जबकि ऐसे कई विभाग हैं जहां विद्यार्थियों का आंकड़ा 100 से अधिक है। विश्वविद्यालय इन विभागों में नियुक्ति करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा है। उक्त मामले में जिस शिक्षक की तैनाती मानी जा रही है उसके संबंध मुखिया से लेकर सत्तासीन पार्टी के लोगों से करीबी हैं।

प्रांत मंत्री ने कहा 37 प्रोफेसरों की भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अब विश्वविद्यालय पुराने नियमों के अनुसार भर्तियां करने जा रहा है, जो उच्च न्यायालय के नियमों के खिलाफ है। प्रांत मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार यह बैकडोर भर्तियां बंद करे, अन्यथा एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। ■

सरस्वती नदी-अंतः सलिला होने को मिला बल

✍ दीपक बरनवाल

हरियाणा के यमुना नगर के आदिबद्री से महज पांच किलोमीटर की दूरी पर अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह विलुप्त नदी सरस्वती की खोज को लेकर खुदाई शुरू हुई। धरातल से महज सात–आठ फीट की खुदाई पर ही वहां जल धारा एकाएक फूट पड़ी। जानकार इसे सरस्वती नदी का जल मान रहे हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग असमंजस में है और इस मामले में कोई टिप्पणी करने से बच रहा है। एक मान्यता के अनुसार प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हालांकि यहां गंगा–यमुना की जलधारा के अलावा सरस्वती नहीं दिखाई देती है। मान्यता है कि सरस्वती नदी अंतः सलिला बनकर बह रही है। आदिबद्री में जलधारा के प्रस्फूटित होने से सरस्वती की अंतः सलिला होकर बहने की मान्यता को बल मिला है।

अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन सभ्यता से मानते हैं लेकिन सरस्वती नदी की खोज से भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब यह माना जाने लगा है कि देश में सिंधु घाटी सभ्यता के इतर भी मानव सभ्यता का इतिहास रहा है जो सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में पनपी। यह विचार अब तक के भारतीय इतिहास के उस नींव को तोड़ेगा और आर्य बाहर से भारत आये थे, इस मिथ्या को झुठलायेगा। सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद् डॉ. स्वराज गुप्त की पुस्तक 'इंडस–सरस्वती सिविलाइजेशन' में सरस्वती नदी की सभ्यता पर एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया है।

सरस्वती एक पौराणिक नदी है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में भारत की दस नदियों में इसका वर्णन है जिसमें सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें सरस्वती नदी को 'यमुना के पूर्व' और 'सतलुज के पश्चिम' मे बहती हुई बताया गया है। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, मनु स्मृति, मेघदूत समेत कई ग्रंथों में सरस्वती नदी की चर्चा है। महाभारत में इसका प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई

नाम हैं। इसमें बताया गया है कि इसी नदी के किनारे ब्राह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। इसमें यह भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी।

एक फ्रेंच प्रोटो–हिस्टोरियन मिशैल डैनिनो ने सरस्वती की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। डैनिनो का कहना था कि करीब पांच हजार वर्ष पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज को पानी मिलता था। यह हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं।

अनुमानित मार्ग के अनुसार सरस्वती का मार्ग पश्चिम गढ़वाल के बंदरपंच गिरि पिंड से निकला होगा। यमुना भी इसके साथ–साथ बहा करती थी और आगे जाकर आपस में मिल गई होगी। यहां से फिर पंजाब, हरियाणा होते हुए राजस्थान और गुजरात के रास्ते अरब सागर में मिल जाती होगी।

इसरो के वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी के लिए कोई स्रोत नहीं है लेकिन यहां कुछ स्थानों पर भूमिगत ताजे पानी के स्रोत हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बारिश बहुत कम होती है। इसके बाद भी यहां 50–60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं सालभर नहीं सूखते हैं। रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि रेत के टीलों के नीचे जमा पानी कुछेक हजार वर्ष पुराना है। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं यह जल भंडार सरस्वती नदी का तो नहीं है!

सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ शिखर के पश्चिम में हर–की–दून ग्लेशियर है। सरस्वती नदी शिवालिक की आदिबद्री से निकलकर हरियाणा, पंजाब, सिंध प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में गिरती थी। सतलज और यमुना इसकी सहायक नदियां थी।

सतलज, यमुना और सरस्वती के उवर्रक डेल्टा और बेसिन के आसपास रिहायशी बस्तियां रही होंगी लेकिन प्राचीन समय में कुछ बड़े व भीषण भूकम्पों के कारण उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल गयी। शिवालिक क्षेत्र 20 से 40 मीटर ऊंचा हो गया। यह बदलाव सरस्वती और सिंधु क्षेत्रों में भी आया। शक्तिशाली भूकंप सरस्वती और इसकी उपधाराओं के पुराने रास्ते बदल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सतलज ने रास्ता बदला और यह पश्चिम में सिंधु नदी से जा मिली और यमुना नदी पूर्व की ओर गंगा के पास आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना और आंतरिक बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई। ■

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की तीन दिवसीय बैठक 27, 28 और 29 मई को महाराष्ट्र के संभाजीनगर (औरंगाबाद) में संपन्न हुई। कार्यकताओं के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए इस बैठक में निम्न पांच प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 1 – प्रादेशिक सरकारी महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो

व्यक्तित्व के समग्र विकास एवं जीवन–स्तर में सुधार का प्रमुख माध्यम शिक्षा है। भारत में शिक्षा के विकास हेतु महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। वर्ष 1950–51 में जहां 578 कॉलेज और 27 विश्वविद्यालय थे, वहां आज लगभग 36,671 कॉलेज और 712 विश्वविद्यालय हो गए हैं। इन महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में देश भर के लाखों छात्रों का भाविष्य तय होता है। इन संस्थानों को सस्ती–गुणवत्तापूर्ण व कौशल युक्त शिक्षा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए परन्तु आधारभूत संरचना का अभाव, अध्यापकों की कमी, वित्तीय कमी, छात्र–छात्राओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, गुणवत्तायुक्त शिक्षा व शोध के अभाव के कारण आज देश के सभी प्रान्तों में सरकारी महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

विगत वर्षों में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति, प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों, परीक्षा व मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं धांधली के मामले कई प्रान्तों में उजागर हुए हैं, जिसके कारण इन संस्थानों की छवि धूमिल हुई है। पूरे देश में शिक्षकों के 6 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। शिक्षकों की नियुक्तियों तथा पाठयक्रमों में समयानुसार बदलाव नहीं होने के कारण छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल पा रही है।

प्रादेशिक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति के लिए राज्य सरकारों की भूमिका संदिग्ध है। सरकारी महाविद्यालय–विश्वविद्याल की व्यवस्था पर्याप्त धन राशि के अभाव में जर्जर हो चुकी है। वर्षों से कॉलेजों का रख–रखाव, साफ–सफाई, पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था दयनीय हो चुकी है। कॉलेजों में वर्षों से पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें और प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक सामग्री खरीदी नहीं गयी है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार मानती है।

अभाविप का मत है कि बड़े पैमाने पर खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण सरकारी संस्थानों की स्थिति और अधिक चिंताजनक बन गयी है। यह कितना दुर्भाग्यजनक है कि पूरे देश में विगत 10 वर्षों में जहां नगण्य मात्रा में कुछ ही सरकारी महाविद्यालय–विश्वविद्यालय खोले गये वहां इसी दशक में निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हजारों की संख्या में खुल गये हैं। उदाहरण के लिए–बिहार जैसे राज्य में 11 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद आज भी केवल 231 सरकारी महाविद्यालय हैं। परिमाणतः राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं चाहकर भी, पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभाविप का स्पष्ट

मत है कि राज्य सरकारें अधिक से अधिक सरकारी महाविद्यालय–विश्वविद्यालय खोले जाएं तथा कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे निजी महाविद्यालयों – विश्वविद्यालयों पर रोक लगाये और इन संस्थानों में राज्य की भाषाओं में सभी विषय पढ़ाया जाना सुनिश्चित करे।

देश के सर्वाधिक छात्रों को शिक्षा देने वाले इन संस्थानों में यदि स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठयक्रमों की रचना की जाय, साथ ही कौशल–विकास को पाठयक्रम में शामिल किया जाये तो ये संस्थान देश व समाज के विकास हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित हो सकते हैं।

अभाविप का मानना है कि वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए यदि प्रातः, सांध्य एवं रात्रिकालीन कक्षाओं का संचालन एवं अध्ययन की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालयों में करें, तो इन संस्थानों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के प्रस्ताव सत्र में उपस्थित प्रतिनिधि

वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय बजट का 4.05% शिक्षा के लिए आवंटित था और मात्र 0.89% उच्च शिक्षा के लिए आवंटित था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र व राज्य सरकारों से मांग करती है कि राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की बुनियादी संरचना के विकास हेतु अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इन संस्थानों की वर्तमान शैक्षिणक परिवेश में और अधिक सक्षम तथा सार्थक बनाने की दिशा में पहल करें।

प्रस्ताव क्र. 2 – देश का वर्तमान परिदृश्य

एक साल पहले सत्ता–परिवर्तन के बाद देश में एक सकरात्मक वातावरण बना है। वर्तमान केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों ने भारत का मान दुनियाभर में बढ़ाया है। यमन से 4000 से अधिक लोगों को गृह–युद्ध के कब्जे वाले क्षेत्र से सकुशल स्वदेश वापस लाना, साथ ही अन्य देशों के नागरिकों को भी सकुशल बाहर निकालना भारत की कूटनीतिक विजय को दर्शाता है। "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ", "जन धन योजना", "मुद्रा बैंक" जैसी केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं ने महिलाओं एवं गरीबों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत की प्राथमिकता देने, मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराने जैसे अनेक सराहनीय कदम भी उठाये गये हैं। कुछ दिन पूर्व नेपाल में आये भूकंप त्रासदी के तुरन्त बाद भारत सरकार ने जो तत्परता दिखायी, उसके द्वारा किया गया राहत व बचाव कार्य प्रशंसनीय है। हम मांग करते हैं कि देश में फैले भ्रष्टाचार, बेकाबू महंगाई, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के चलते किसानों की हो रही आत्महत्याओं पर रोक लगाने व विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के संदर्भ में समस्त देशवासियों की अपेक्षाओं को भी वर्तमान केन्द्र सरकार शीघ्र पूरा करे।

कई दशकों से देश में चल रहा माओवाद समय–समय पर अपनी देशद्रोही तथा हिंसक घटनाओं के द्वारा समाज को चिन्तित करता रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की हुई नृशंस हत्याएं एवं राष्ट्र–विरोधी घटनाएं इसका उदाहरण है। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जैसे अन्य जिलों में विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा का अभाविप स्वागत करती है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि वह माओवाद को जड़ से समाप्त करने हेतु कठोर कदम उठाए।

गत कुछ महीनों में जम्मू–कश्मीर में उत्पन्न हुई परिस्थिति तथा पाक–समर्थित आतंकी हमलों पर अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। हुर्रियत की कश्मीर में हुई रैलियों में खुलेआम पाकिस्तानी झंडे लहराना व पाक–समर्थन में नारे लगाना, लगातार सीमा पार से गोलीबारी तथा मोर्टार दागे जाना, सुरक्षा बलों पर नियमित रूप से हमले होने के बावजूद जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा आतंकवादियों के प्रति नरम रूख अपनाए जाने की अभाविप निंदा करती है तथा केन्द्र सरकार से इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करती है।

कुछ दिनों पूर्व अभिनेता सलमान खान तथा तमिलनाडू की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता केस में न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों पर देश की आम जनता के मन में क्षोभ व्याप्त है। देशभर के न्यायालयों में लाखों मामलें लंबित होना, हजारों जजों के पद रिक्त होना तथा निर्णय–प्रक्रिया में वर्षों बीत जाने जैसी गम्भीर परिस्थिति के कारण आज देश में न्यायपलिका में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देर से मिला न्याय अन्याय के समान है। अतः न्यायपालिका पर सामान्य जनों का विश्वास कायम रखने के लिये केन्द्र सरकार न्यायिक सुधार के विषय में तुरंत पहल करे।

हाल ही में यूपी–पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न–पत्र लीक होने के मामले ने देश को खोखला कर रहे भ्रष्टाचार को एक बार फिर उजागर किया है। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं पर आगरा में रासुका लगाने तथा इलाहाबाद में बेरहमी से किये गये लाठीचार्ज की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् निंदा करती है। इसी प्रकार शिक्षा के मुद्दों को लेकर पटना में हुई अभाविप की रैली पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज एवं हवाई फायरिंग की अभाविप निंदा करती है। आज पश्चिम बंगाल की वर्तमान ममता बनर्जी सरकार के कारण कॉलेज एवं विश्वविद्यालय परिसर राजनीतिक हिंसा का केन्द्र बन गये हैं। विगत छात्र–संघ चुनावों में एवं उसके बाद भी राजनीतिक हिंसा तथा प्रतिशोध के चलते कई निर्दोष छात्रों के साथ–साथ विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं पर हमला करना, सिगरेट से जलाना, उन पर गोली चलाना, नामांकन नहीं होने देना आदि घटनाओं की अभाविप तीव्र भर्त्सना करती है।

महिला सुरक्षा का मुद्दा आज भी देश के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। पश्चिम बंगाल में नन के साथ सामूहिक बलात्कार, पंजाब में हुए मोंगा बस कांड जैसी घृणित घटनाओं पर अभाविप चिंता व्यक्त करती है। अभाविप केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मांग करती है कि महिला सुरक्षा हेतु बने कानून को कठोरता से लागू कर महिलाओं का सम्मान बनाए रखें, साथ ही समाज से यह आह्वान करती है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा व सम्मान का अहसास कराने में वह भी अपनी भूमिका निभाए।

देश के युवाओं ने कई आशाओं व अपेक्षाओं के साथ वर्तमान केन्द्र सरकार को अपार बहुमत से चुनकर सत्तासीन किया है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से अपेक्षा करती है कि युवाओं

(शेष पृष्ठ 27 पर...)

ईशान्य मुंबई में 'समुराई' समर कैंप का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ईशान्य मुंबई की ओर से 11 से 14 मई, 2015 इन चार दिनों में 'समुराई' समर कैंप (ग्रीष्म कालीन चल शिविर) का आयोजन किया गया था। यह समर कैंप दिव्य विद्यालय जव्हार एवं पिंजाल नदी के पहाड़ी वनक्षेत्र में उत्साह पूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जहाँ स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक बिजली नहीं पहुंची, पानी के लिए जहाँ जनजाति बंधुओं को कोसों दूर पहाड़ों को लांघते हुए भटकना पड़ता है, किसी भी मोबाईल को जरा सी भी रेंज जहाँ मिलती नहीं, वहाँ मुंबई के 59 छात्रों ने दो दिन तक अपनी जरूरतों को अपेक्षा से भी ज्यादा कम करते हुए, जनजाति बंधुओं के प्रति सामाजिक संवेदना का भाव रखते हुए जो कार्य किया उस से यह प्रतीत होता है कि इन छात्रों ने सही मायने में 'समुराई' होने का प्रमाण दिया है।

इस शिविर में छात्रों ने जनजाति पाड़ों में जाकर जनजाति बंधुओं की हर समस्या के निराकरण करने हेतु मुंबई के लोग भी आपके साथ हैं यह भाव उन बंधुओं में निर्माण करते हुए उन परिवारों के साथ जब स्नेह भोजन किया तो अपनेपन की भावना जागृत होने में मदत हुई।

इस शिविर में रोज प्रातः समय विचारकणिका श्रमानुभव और साथ में Time management, Positive Attitude, Camp Fire, Team Building, मशाल सत्र, आकाश दर्शन, अभाविप कल आज और कल, पथनाट्य, जनजाति बंधुओं के घरों में भोजन आदि सत्र एवं गतिविधियाँ हुई। इस शिविर में 34 छात्र, 19 छात्राएं सहित कुल 59 लोग उपस्थित थे। ■

कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से रूक सकती है कन्या भ्रूण हत्या

जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइव ईयर लॉ कॉलेज में कन्या भ्रूण हत्या विषय पर कार्यशाला हुई। जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। अभाविप के प्रदेश सह मंत्री शंकर गौरा ने बताया कि कार्यशाला में सत्यमेव जयते फेम श्रीपाल शक्तावत, डा. सुशीला शर्मा, आईएएस नीरज के. पवन, डा. मनीषा शर्मा आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर शक्तावत ने कहा कि देश में हर दूसरे मिनट 5 कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने इसे रोकने के लिए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को जरूरी बताया। कार्यक्रम संयोजक मोहन मिश्रा व अखिलेश पारीक ने बताया कि संगोष्ठी में 7 विश्वविद्यालय के विधि एवं पत्रकारिता के 577 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ■

'हम सब जन्म से योगी' - श्री श्री रविशंकर

योग से कई हितकारी लाभ है। सबसे पहला लाभ यही कि इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। योग तनावमुक्त और थकान रहित जीवन के लिए एक उपकरण और तकनीक के रूप में उपलब्ध है। योग मानव समाज की सबसे बड़ी दौलत है। दौलत क्या है? दौलत का उद्देश्य जीवन में खुशी और आराम पाना है। 'आराम' के मामले में योग धन है, जो पूर्णतः आराम प्रदान करता है।

हिंसा मुक्त समाज, रोगमुक्त शरीर, भ्रम से मुक्त मन, अवरोध मुक्त बुद्धि, आघात मुक्त स्मृति और दुख से मुक्त आत्मा मिले, यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनियाभर के तमाम संसद मानव अस्तित्व के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

हम सभी अपने लोगों की खुशी चाहते हैं और योग ही वह रास्ता है जहां से सबको जीवन में आवश्यक खुशी मिलेगी।

हम सोचते हैं कि योग व्यायाम के कुछ प्रकार हैं। अस्सी और नब्बे के दशक में मै जब यूरोप के दौरे पर होता था, तब योग को मुख्य धारा से जुड़ा समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था।

आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि वहां के लोग जागरूक हो रहे हैं, योग के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। पूरे विश्वभर में योग आराम, खुशी और रचनात्मक का पर्याय बन गया है। आज बड़ी–बड़ी कंपनियां अपने विज्ञापनों में मन की शांति के लिए लोगों की योग करते व ध्यान करते हुए दिखाये लगे हैं।

हम इस बात को स्वीकार करें या न करें। यह एक सच्चाई है कि हम सब जन्म से योगी हैं। अगर आप छोटे मासूम बच्चे पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और उसे देखेंगे तो आपको योग शिक्षक की कमी जरूरत महसूस नहीं होगी। **विश्वभर में किसी भी बच्चे को देख लो, जिनकी उम्र तीन माह से लेकर तीन साल की है, वे सभी योग मुद्राओं को दोहराता रहता है। बच्चे का श्वास लेना, उसके सोने का तरीका, उसके मुस्कुराने का सलीका सब योग है। एक बच्चा कुशल योग शिक्षक है, सम्पूर्ण योगी है। यही कारण है कि बच्चा तनाव मुक्त रहता है, वह दिन में चार सौ बार मुस्कुराता है।**

योग करने से एक और महत्वपूर्ण लाभ होता है, वह यह कि इससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के तनाव का स्तर काफी हद तक उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। योग दोस्ताने स्वभाव को पैदा करता है और इससे सुखद वातावरण तैयार होता है। योग हमारे गैस्चर और पोस्चर को बेहतर बनाता है जिसका उपयोग संवाद स्थापित करने के क्रम में शब्दों से कहीं अधिक उसका प्रभाव करते हैं। क्वाटंम यांत्रिकी की थ्योरी के रूप में कहें तो, हम सब एक दूसरे के लिए तरंग उत्पन्न करते है।

संवाद करने की हमारी क्षमता हमेशा दूसरे से संचार प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब हमारे तरंग नहीं मिलते जो संचार टूट जाता है और संवाद क्रम रूक जाता है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है और आंतरिक कौशल को विकसित करने में मदद करता है।

योग का प्रतिपादन करने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवत में कहा है कि योग कार्यवाही करने का कौशल है। योग केवल व्यायाम नहीं है, वह आपको कैसी भी परिस्थिति में काम करने और संवाद स्थापित करने की क्षमता को विकसित करता है।

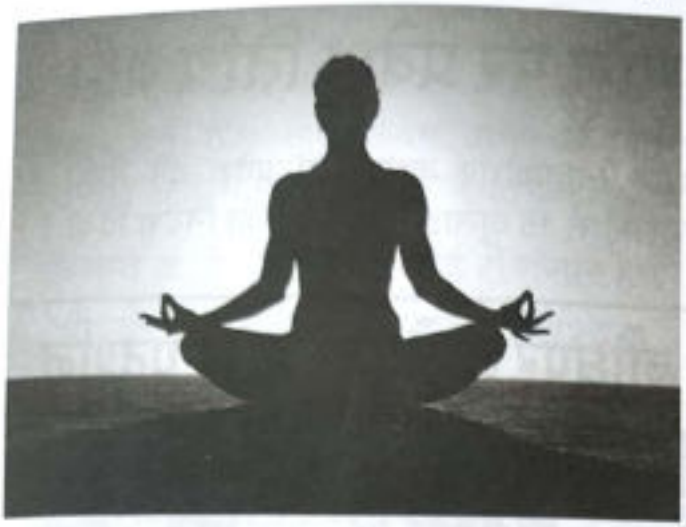

अभिनव, अंतर्ज्ञान, कौशल और बेहतर संचार सब पर योग का प्रभाव है। योग हमेशा विविधताओं में सद्भाव को बढ़ाता देता है। योग शब्द का तात्पर्य अपने आप एकजुटता से है, जीवन के अस्तित्व के सभी विविध पहलुओं को एकजुट करना ही योग है। व्यक्ति चाहे व्यापारी हो या कोई हस्ती या कोई और, सबको शांति चाहिए, हर कोई खुश रहना चाहता है, मुस्कुराना चाहता हैं।

खुशियां तभी संभव है जब हम दुख के कारण के मूल को देखेंगे। दुख हमेशा दबाव, तनाव और देखने की क्षमता में कमी के कारण होता है।

यूरोपीयन संघ जी डी एच के बारे में बहुत बात करता है। हम लोग भी सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) से सकल घरेलू सुख (जी डी एच) की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योग इसके लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण हो सकता है। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा अवसाद से पीड़ित है। अवसाद विरोधी तत्व से इसकी मदद नहीं हो सकेगी।

हमारा श्वास प्राकृतिक है। हम श्वास का उपयोग अपने मन और आत्मा के विकास में कर सकते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखना योग की क्रियाओं को अपनाता है। योग का उद्देश्य हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन में होने वाले तनाव, दबाव पर नियंत्रण रखते हुए हर स्थिति में चेहरे पर मुस्कान लाना है। ■

(अनुवाद : दीपक बरनवाल)

कॉलेज में एबीवीपी का हेल्प सेंटर शुरू

शिवपुरी (मप्र)। एबीवीपी द्वारा पीजी कॉलेज में छात्रों की समस्या के समाधान के लिए 25 जून को एक सहायता केंद्र शुरू किया गया है। इस समय चल रही प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एबीवीपी के छात्र इस केंद्र के जरिए छात्रों की मदद करेंगे। गुरुवार को इस केंद्र का शुभारंभ एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री नवनीत सेन, जिला संयोजक आशीष बिंदल ने किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष विवेक उपाध्याय ने बताया कि इस समय चल रही रजिस्ट्रेशन व वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को जो परेशानी आती हैं उनके निराकरण के लिए यह हेल्प सेंटर मदद करेगा। ■

नशामुक्त पर्यावरण युक्त स्वच्छ भारत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नशा मुक्त पर्यावरण युक्त विषय को लेकर 'PAINTING AND SLOGAN WRITING' का कार्यक्रम विवेकानन्द पार्क, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में रखा गया। जिसमें जयपुर महानगर के विभिन्न महाविद्यालयों और राजस्थान ने भी कैनवास पर पेंटिंग्स बनायीं एवं स्लोगन लिखे।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हनुमान सिंह भाटी भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रत्येक पेंटिंग का अवलोकन किया और कार्यक्रम की प्रशंसा की। ■

मध्य प्रदेश में अभाविप की मांग पर प्रवेश तिथि बढ़ी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हमेशा से ही छात्र हितों के लिये संघर्षरत है। पहली जुलाई को मध्यभारत प्रांत में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ाने के लिये उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्रांत के समस्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों को अभाविप द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रवेश की तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ाने का निर्देश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिया।

मध्यभारत प्रांत के मंत्री श्री रोहिन राय ने बताया कि पूरे प्रांत में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को ज्ञापन सौंपे गये। जिसमें इन्दौर, धार, देवास, उज्जैन, मन्दसौर, नीमच, भोपाल, ग्वालियर, गुना, हरदा, मुरैना, शिवपुरी आदि जिलों के 189 से अधिक कॉलेजों में हजारों को संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहले कॉलेज में प्रदर्शन और नारेबाजी की उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्यों को ज्ञापन सौंपा।

श्री रोहिन राय ने बताया कि मध्यप्रदेश में अभी भी कई विश्वविद्यालय ऐसे है, जिनके परीक्षा परिणाम नहीं आये है। वहीं 12वीं में कई छात्र–छात्राओं की सप्लीमेंट्री भी आई थी जिससे वे भी अभी तक प्रवेश नहीं ले पाये है। प्रदेश में लगभग 56 हजार से ज्यादा छात्र–छात्राएँ अंतिम तिथि समाप्त हो जाने तक अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन भी नहीं करा सके।

ऐसे में म. प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरों के भी ऐसे कई हजार छात्र अभी भी प्रवेश से वंचित है। यूजी और पीजी में प्रवेश के लिये पंजीयन और मूल दस्तावेज की दिनांक 10 जुलाई तक आगे बढ़ाने की मांग अभाविप ने की है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में छात्र–छात्राओं को ऑफलाइन प्रवेश भी दिये जाने की मांग की।

छात्र–छात्राओं के भविष्य को देखते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की तिथि 07 जुलाई से 15 जुलाई तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।

जोधपुर में जेएनवीयू में प्रदर्शन

जोधपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में की विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया।

अभाविप विभाग संयोजक महेन्द्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में केन्द्रीय कार्यालय पर छात्रों ने सुबह नारेबाजी की। कुलपति ने अभाविप की मांगों पर उचित समाधान का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में केएन कालेज में एकल खिड़की उपलब्ध करवाना, बीए व एमए के परिणाम जल्द घोषित करना, शुल्क जमा करवाने के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाने, विश्वविद्यालय की मूल अंकतालिका परिणाम के एक सप्ताह में उपलब्ध करवाने, विद्यार्थियों की हार्डकापी जमा कराने के लिए 28 जून तक का समय देने,विश्वविद्यालय की कक्षाओं व छात्रावासों की आधारभूत व्यवस्था सुधारने, विश्वविद्यालय के सभी संकायों में सेल्फ सेक्शन बढ़ाने, कॉमर्स व कला संकाय को दो बजे तक खुले रखने सहित कई मांगें शामिल हैं।

■

(पृष्ठ क्र. 22 से...)

से किये गये वादों को पूरा करने व युवाओं के रोजगार हेतु शीघ्र ठोस कदम उठाए व घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे।

प्रस्ताव क्र. 3 - उद्यमिता एवं रोजगार हेतु कौशल-संवर्धन की योजना आवश्यक

देश में 35 वर्ष से कम आयु की दो–तिहाई जनसंख्या के साथ, भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 25% भारतीय प्रोफेशनल ही संगठित क्षेत्र द्वारा रोजगार के लिये उपयुक्त समझे जाते हैं। एक अन्य रिपोर्ट में देश की कुल कार्मिक शक्ति का 10% ही कौशल सम्पन्न है, जबकि विकसित देशों में यह कई गुना अधिक है, जैसे दक्षिण कोरिया में यह 95% है।

अभाविप मानती है कि 'मेक इन इंडिया' जैसी बृहत योजनाओं से आगामी समय में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, परन्तु देश के युवाओं में स्वरोजगार व कौशल–विकास की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक कौशल–संवर्धन योजना की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् सरकार द्वारा 34 मंत्रालयों एवं 173 योजनाओं को मिला कर 'कौशल संवर्धन एवं उद्यमिता मंत्रालय' बनाए जाने का स्वागत करती है। साथ ही मांग करती है कि सरकार खेती, पारम्परिक पेशे से जुड़े कुटीर उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र में अनुभव के आधार पर प्राप्त कौशल को सत्यापित करने का प्रबन्ध करे ताकि समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

विद्यार्थी परिषद् मानती है कि विद्यार्थियों को उद्यमी एवं रोजगारक्षम बनाने हेतु 9वीं कक्षा से ही कौशल संवर्धन से जुड़े पाठ्यक्रम चलाने चाहिए तथा महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों में कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रमों को स्वरोजगार के स्थानीय अवसरों को देखते हुए पूरी शक्ति से लागू करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक एवं व्यक्तिगत कारणों से स्कूल तथा महाविद्यालयों में शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले युवाओं को कौशल–संवर्धन के साथ–साथ आर्थिक सहायता एवं आसान शर्तो पर बैंक–ऋण उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए। अभाविप मांग करती है कि सरकार सभी 30 कौशल–संवर्धन परिषदों के माध्यम से निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठनों एवं शिक्षण संस्थानों को कौशल–संवर्धन से जोड़े। वस्तुतः देश में लघु और कुटीर उद्योगों की नई श्रृंखला खड़ी करने में समाज के सभी अंगों का सहयोग अपरिहार्य है।

आज आवश्यक है कि देश में 'एक युवा–एक कौशल' का न्यूनतम स्तर स्थापित किया जाए, जिससे युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता का मार्ग प्रशस्त हो। इसी कड़ी में अभाविप युवाओं को आह्वान करती है कि वे भी स्वयं को कौशल–सम्पन्न बनाकर रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी एवं राष्ट्र–निर्माण में रोजगारोपयोगी साबित हों।

प्रस्ताव क्र. 4 - विद्यार्थियों के छात्रावासों व छात्रवृत्ति की स्थिति में अविलम्ब सुधार हो

देश के युवाओं के लिए आज शिक्षा एवं समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हुए हैं। नव शिक्षित युवाओं को मिली सामाजिक व आर्थिक प्रतिष्ठा ने देशभर के युवाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक पैदा की है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र–छात्राओं में भी उच्च शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा है। आज अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्र–छात्राएं अधिक संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु तत्पर हैं, परन्तु शासकीय योजनाओं का सुचारू संचालन व सुदृढ़ व्यवस्थापन नहीं रहने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में रह रहे

छात्र–छात्राएं अध्ययन हेतु अव्यवस्थाओं के बीच रहने को मजबूर हैं। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 2002–03 तक जनजाति छात्र–छात्राओं के लिए 1392 छात्रावास बनने थे। इसकी राशि भी आवंटित की गयी थी, लेकिन केन्द्र सरकार की ही वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2012–13 तक मात्र 851 छात्रावासों का ही निर्माण हो पाया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने विगत वर्षों में संपूर्ण देश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों का व्यापक सर्वे किया था। देशभर के 231 जिलों के 1110 छात्रावासों में किये गये व्यापक सर्वे ने इन छात्रावासों की वास्तविक स्थिति को उजागर किया। व्यापक सर्वे को आधार बनाकर अभाविप ने वर्ष 2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत सात सालों में हर सुनवाई में, अलग–अलग राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार से जानकारी मांगी थी। उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 30 जनवरी, 2015 को अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों की व्यवस्थताओं को ठीक करने के लिए 4 माह का समय देते हुए, उस संदर्भ में अब तक की गई कार्यवाही (Status Report) से अवगत कराने को कहा है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् माननीय सर्वोच्च न्यायलय की इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत करती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का स्पष्ट मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र–छात्राओं के अध्ययन–अध्यापन हेतु जो राशि आवंटित की जाती है, राज्य सरकारें उसका बड़ा अंश दूसरे मदों में खर्च करती है जो कि सरासर गलत है। अभाविप का मत है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं के अध्ययन–अध्यापन हेतु आवंटित की गयी राशि व योजनाओं का यदि सभी राज्य सरकारें समुचित क्रियान्वयन समय पर करें तो स्थिति में तत्काल सुधार आ सकता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र व राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों की स्थिति में अविलम्ब सुधार लाने हेतु निम्नलिखित मांग करती है–

1. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित सुविधाओं व योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो एवं छात्रावासों की आधारभूत संरचना को अद्यतन रूप से व्यवस्थित किया जाय।
2. देश में मूल्य सूचकांक के आधार पर SC/ST विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का निर्धारण हो।
3. बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए छात्रावासों की संख्या व व्यवस्थाएँ बढ़ायी जाये।
4. SC/ST शोधार्थियों को प्रदत्त राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप हेतु निर्धारित 667 सीटों को, वर्तमान संख्या के अनुरूप बढ़ाया जाय। (सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006–07 में 5523–SC/ST छात्र–छात्रा शोध हेतु पंजीकृत थे, तो भी R.G.N.F. शोधवृत्ति 667 छात्र–छात्राओं को ही मिलती थी और वर्तमान में भी स्थिति यथावत् है।)
5. छात्रावास में रहने वाले छात्र को, राजकीय अस्पताल द्वारा 'छात्र स्वास्थ्य पत्र' (Student Health Card) उपलब्ध करवाया जाय एवं सरकारी खर्चे पर स्वास्थ्य–सुविधा दी जाय।
6. वर्तमान बदलते हुए सामाजिक–परिवेश के

अनुसार छात्रावासों में संगणक (Computer), इंटरनेट, वाचानलय समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

7. सभी छात्रावासों में विशेष रूप से कन्या छात्रावासों में सुरक्षा, स्वास्थ्य–परीक्षण इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं कन्या छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक, वार्ड परिचारिका तथा अन्य पदों पर महिलाओं की ही नियुक्ति निर्धारित हो।

8. जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ–साथ SC/ST छात्र–छात्राओं की 'सम्मिलित क्रियान्वयन समिति' का प्रावधान सुनिश्चित हो, इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।

9. छात्र–छात्राओं की रोजगारपरकता बढ़े, इस दृष्टि से छात्रों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना सुनिश्चित हो।

10. छात्रावास में उत्कृष्ट खेल–सुविधा व खेल कोच की स्थायी व्यवस्था के साथ–साथ इन छात्र–छात्राओं के लिए प्रान्त व राष्ट्रीय स्तर पर खेल–कूद प्रतिस्पर्धा का आयोजन सुनिश्चित हो।

प्रस्ताव क्र. 5 – शैक्षिक जगत् में बढ़ते व्यापारीकरण पर लगाम लगे

आदिकाल से भारतीय परम्परा में शिक्षा केवल राज्याश्रित न होकर समाज द्वारा संचालित होती रही है। ऐसे में, शिक्षा क्षेत्र में निजी सहभागिता को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अनुचित नहीं मानती है। किंतु वर्तमान समय में, निजीकरण के नाम पर शिक्षा का व्यापारीकरण लगातार बढ़ रहा है। इससे शिक्षा सामान्यजनों की पहुंच से दूर होती जा रही है।

पिछले दो दशकों में देश में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़–सी आ गयी है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापारीकरण कई गुना बढ़ा है। एक सर्वे के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की उम्र के 29% विद्यार्थी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आज देश मे निजी प्रादेशिक विश्वविद्यालयों की संख्या 185 तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। अधिकतर निजी विद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। नियामक संस्थानों की सीमित शक्तियां तथा ढुलमुल रवैये के कारण आज इन संस्थानों में विद्यार्थियों को मोटी फीस चुकानी पड़ रही है। अभाविप गैर सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने व इनके शुल्क एवं प्रवेश के नियंत्रण हेतु कानून की मांग करती है।

अभाविप का यह सुविचारित मत है कि देश के निजी शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता, आधारभूत संरचना, पारदर्शी प्रवेश व शुल्क–संरचना इत्यादि सुनिश्चित करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही, शैक्षिक क्षेत्र की समस्त नियामक संस्थाओं का समय की आवश्कतानुसार पुनर्गठन या उनकी भूमिका में बदलाव की भी आवश्कता है। निजी शिक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे फर्जीवाड़े का रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक शैक्षिक न्यायाधिरण (Educational Tribunal) की स्थापना की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से शैक्षिक क्षेत्र में बड़े सुधार हेतु एक सम्यक दृष्टि अपनाते हुए, एक व्यापक केन्द्रीय कानून लाने की मांग करती है, जिससे शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने तथा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती व सर्वसुलभ बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। ■

डीयू के सेंट स्टीफंस में अभाविप ने मांगा प्रिंसिपल का इस्तीफा

नई दिल्ली। डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज में यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता द्वारा कॉलेज प्रिंसिपल वाल्सन थंपू का स्टिंग करने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा पीड़िता से आरोप वापस लेने की बात प्रिंसिपल द्वारा कहने पर अब कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज बुलंद कर दी है।

शुक्रवार को स्टीफंस कॉलेज के बाहर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की। डीयू छात्र संघ कार्यालय से लगभग ढाई सौ छात्र जुलूस निकालते हुए सेंट स्टीफंस कॉलेज पहुंचे। छात्र कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके ऑफिस तक पहुंचे लेकिन वहां ताला लटका मिला।

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा ने बताया कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का वाक्या शर्मशार करने वाला है। कॉलेज प्रिंसिपल की इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम स्टीफंस के प्रिंसिपल के इस्तीफे की भी मांग करते हैं।

शोध की छात्रा की माने तो कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसके साथ छेडछाड की और थम्पू ने उस प्रोफेसर को बचाने का प्रयास किया। पीडिता ने पिछले हफ्ते पुलिस से संपर्क कर चार रिकॉर्डिंग सौंपे जिसमें दावा किया कि प्रिंसिपल के साथ मुलाकात के दौरान ये रिकॉर्डिंग की गई जिन्होंने उसे शिकायत वापस लेने का कथित तौर पर दबाव बनाया। ■

फर्जीवाड़े को लेकर विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से अंकतालिका बनाये जाने को लेकर विश्वविद्यालय परिसर और डीसी आफिस के बाहर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना–प्रदर्शन किया। एबीवीपी के प्रांत मंत्री आशीष सिक्टा ने धरने को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण एसएफआइ नेता फर्जी अंकतालिकाएं बना रहे हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा पहले भी सामने आ चुका है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

आपको बतादें कि यह मामला पिछले महीने 12 जून को प्रकाश में आ गया था बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर हो जाता है विश्वविद्यालय के प्रशासन की मिलीभगत से यह मामला हुआ है। इतना ही नहीं यहां परीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

धरने को संबोधित करते हुए इकाई सचिव चेतन गुलेरिया ने कहा कि वित्त कमेटी की बैठक को बार बार टाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के भीतर बैकडोर भर्तियां हो रही हैं। सरकार अपने चहेतों को विवि के भीतर भर्ती करने के कार्य कर रही है। इसलिए गुपचुप तरीके से नियमों में फेरबदल किये जा रहे हैं। धरने में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक की कुछ झलकियां

RNI No. 32464/78

आँगनवाड़ी में पहले शिक्षा उसके बाद पहली कक्षा

जीवन के प्रथम 6 वर्ष बच्चे के संपूर्ण जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन वर्षों में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र होती है। इसलिए आपके बच्चे के लिए शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा जरुरी है, इससे –

- स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयारी में मदद मिलती है।
- आँगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के विकास की नियमित निगरानी की जाती है।
- नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा पोषण आहार के कारण वे स्वस्थ्य रहते है।
- बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक व भाषाई विकास होता है।

तो फिर अपने बच्चे का नाम अपने पास के आँगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज कराईये

आँगनवाड़ी चलो अभियान

15 से 22 जुलाई 2015

– अभियान की मुख्य गतिविधियाँ –

पहला दिन- वृक्षारोपण एवं खेलकूद प्रतियोगिता
दूसरा दिन- आंगनवाड़ी केन्द्रो की सफाई
तीसरा दिन- चित्रकला/ पोस्टर प्रतियोगिता
चौथा दिन- श्रेष्ठ बालक–बालिका
पांचवां दिन- दादी –नानी संवाद
छटवां दिन- मंगल दिवस
सातवां दिन- बाल सभा का आयोजन

आँगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं/सुविधाओं को उन्नत करने, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने में आप भी योगदान करिये।

ऐसे 20 बच्चें जिनकी आंगनवाड़ी केन्द्रों में विगत तीन माह में उपस्थिति 0 से 5 दिन प्रति माह रही है, अभियान के दौरान किन्ही चार दिनों में प्रतिदिन 5 बच्चों के परिवार से मिलकर उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाऐं नियमित लेने के लिए प्रेरित किया जावेगा।

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्वस्थ बचपन बेहतर भविष्य
राह दिखाती आँगनवाड़ी

आँगनवाड़ी चलो